during 1991-92 and the production targets fixed fro are as under:-

(In Nos.)

	Actuals during 1991-92	Targets fixed for 1992-93
Two Wheelers	1712	12,000
Three Wheelers	2994	48,000
Fans	95168	60,000

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) Scooters India Lmited (SIL) has been referred to Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). After getting the recommendations of BIFR, a final decision will be taken as to the future of SIL.

Decrease in price of "wheel" detergent by Hindustan Lever Limited

3156. SHRI N. GIRI PRASAD; Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether Hindustan Lever Limited has decreased the price of wheel, its low priced detergent, to gradually wipe out the small scale sector from the field;

(b) if so, what is Government's reaction to such a development; and

1c) the action proposed to be taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SHRIMATI KRISHNA SAHI); (a) It is understood that Mis. Hindustan Lever Ltd. has decreased the wrapper prices of its detergent "wheel" from Rs. 4.00 to Rs. 3.60 per cake of 250 gms and from Rs. 2.25 to Rs. 1.80 per cake of 125 gms recently. Its impact on Other detergent manufacturers is, however, not known.

(b) and (c) Synthetic Detergent Industry is in the delioensed sector and there is no statutory price control over prices of soaps and detergents.

ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए आवंटन में कटौती

3157. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए किये जाने वाले धनराशि के आवंटन में कमी की है ;

(ख) यदि, हां तो इस संबंध में कटौती क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए आवंटित की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान धनराशि के आवंटन में कमी किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) : (क) जी नहीं । 1992–93 के दौरान, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के जरिये इस विभाग द्वारा योजनागत स्कीम के तहत ग्रामीण उद्योगों के लिए 19100 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। 1991–92 के दौरान बजट प्रावधान भी इसी स्तर पर था । लेकिन बजट प्रावधान के अलावा पुनः-विनियोग द्वारा 200 लाख रुपय आवंटित किये गये